5. अधिकतम 75 करोड़ रुपये के आधार पर जवाहर रोजगार योजना की 5% निधियां ऐसी योजनायें शुरु करने के लिए निर्धारित की जाएंगी जिनका उद्देश्य मजदूरों के पलायन को रोकना, महिला रोजगार में वृद्धि करना है, स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से विशेष कार्यक्रम जिनका उद्देश्य सूखे पर रोक लगाना तथा वाटर शैड विकास/बंजरभूमि विकास करना है जिसके परिणामस्वरूप सतत् रोजगार प्राप्त होता है ।

6. मजदूरी और गैर-मजदूरी घटक के लिए खर्च को विद्यमान 60:40 के अनुपात में रखा गया है लेकिन कुल मजदूरी के 10% की अधिकतम सीमा के आधार पर अकुशल मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी को मजदूरी घटक के अंतर्गत शामिल करने की अनुमति है ।

समन्वित ग्रामीण विकास योजना के बारे में मेहता समिति

4028. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :**
श्री विरेन जे० शाह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समन्वित ग्रामीण विकास योजना के कार्यान्वयन के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के लिए श्री डी० आर० मेहता की अध्यक्षता में समिति कब गठित की गई थी और उसने सुधार के बारे में अपनी सिफारिशें कब दी थी और क्या सरकार को समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सुझाव दिए गए हैं और उसके कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य योजना तैयार की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) अक्तूबर, 1993 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर श्री डी० आर० मेहता की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सभी पहलुओं की समीक्षा करेगी । समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में पक्की सड़कों से जुड़े हुए गांव

4029. **श्री राघव जी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में एक हजार से अधिक जनसंख्या वाले ऐसे कितने गांव हैं, जो पक्की सड़कों से नहीं जुड़े हैं;

(ख) इन गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार इन गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए राज्य सरकार को विशेष सहायता प्रदान करेगी; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई पटेल) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1992-93 के अन्त तक मध्य प्रदेश में 1000 से अधिक जनसंख्या वाले ऐसे 1900 गाव थे जिन्हें बारहमासी सड़कों से नहीं जोड़ा गया था ।

(ख) और (ग) गांवों को सड़कों से जोड़ना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य का विषय है । ग्रामीण सड़कों के लिए निधियां राज्य/योजना/बजट में उपलब्ध कराई जाती हैं । योजना आयोग न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए निधियां निर्धारित करता है ताकि इन निधियों के अन्य सड़क योजनाओं/परियोजनाओं पर खर्च किये जाने को रोका जा सके ।

Supply of Drinking Water in Andhra Pradesh

4030. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether any special programme for drinking water supply in villages would be implemented for the dry and scanty rain-fed area in Andhra Pradesh;

(b) whether Government are aware of the need to implement special programmes in Nalgonda, Warangal, Karim Nagar and other districts of Andhra Pradesh; and

(c) if so, the steps taken in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

The Schemes for drinking water supply in rural areas are implemented under the normal plan Programmes of Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission/Accelarated Rural Water Supply Programme and Minimum Needs Programme.

Non-operating XRF unit at CFRI, Dhanbad

4031. SHRI A. NALLASIVAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether the Central Fuel Research Institute, Dhanbad purchased one XRF